क्षेत्र के कारखानों के प्रबंध को लोकतांत्रिक बनाया जाए ताकि उनके प्रबंध में कामगार भी पूरी तरह भागीदार हो सकें।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति समाप्त की जाए ।

(4) एल्यूमिनियम उद्योग के मजूरी ढांचे में सुधार किया जाए और उसे इस्पात उद्योग के अनुरूप बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्रबंधकों और कामगारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए।

(5) बिजली सप्लाई की कटौती के कारण उत्पादन में कमी होने पर कामगारों को प्रोत्साहनों सहित पूरी मजूरी की गारण्टी दी जाए ।

सरकार की क्रम-वार प्रतिक्रिया इस प्रकार :---

(1) सरकार ने हिंडालको के ग्रहीत बिजली घर के विस्तार की मंजूरी दे दी है । अन्य एल्यूमिनियम उत्पादकों से ग्रहीत बिजली-घरों की स्थापना हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र मे प्रस्तावित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की योजना मे एक ग्रहीत बिजली घर का प्रावधान है ।

(2) परिस्थितियोंवश जरूरत होने पर एल्यूमिनियम कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाएगा । कारखाना-प्रबंध मे श्रमिकों की भागीदारी के बारे में सरकार द्वारा किए गए नीति संबंधी निर्णय को एल्यूमिनियम उद्योग पर भी लागू किया जाएगा।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य नीति अक्तूबर, 1978 से समाप्त कर दी गई है ।

(4) और (5) चूंकि यह उद्योग सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में है और अधिकतर उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है तथा कंपनियां, भिन्न-भिन्न वित्तीय क्षमताओं सहित, काफी भिन्न हालतों में काम करती हैं, इसलिए इन सुझावों को स्वीकार करना या कार्यान्वित करना संभव नहीं है ।

वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण

773. **श्री रामावतार शास्त्री:**

श्री पीयूष तिरकी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) सरकार, कर पद्धति की सतत समीक्षा करती रहती है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम के संबंध में फ्रांस का प्रस्ताव

774. **श्री नन्द किशोर शर्मा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस सरकार ने भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार इस कार्यक्रम के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ). फ्रांसीसी सरकार ने औद्योगिक और व्यापार सहयोग के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की पेशकश की है । संबंधत मंत्रालय/विभाग इन प्रस्तावों की